DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times NEW DELHI SATURDAY APRIL 22, 2023

Painted Lady

Large Cabbage White

Asian Cabbage White

Tropical Indian Fritillary.
PICS. CHANDRA BHUSHAN MAURYA

Warm Feb and wet March hasten butterflies' arrival

Jasjeev Gandhiok
jasjeev.gandhiok@hindustantimes.com

NEW DELHI: With a relatively warm February in Delhi and the National Capital Region, followed by a wet March with three times the normal rainfall, butterfly enthusiasts have spotted butterfly species migrating to Delhi one to two months earlier than usual.

Since the end of February, butterflies such as the Painted Lady, Blue Tiger, Asian Cabbage White, and Large Cabbage White have been seen in large numbers in several locations across Delhi-NCR, according to experts who track their movement.

These butterflies typically breed in the Himalayan region in April and then migrate to Delhi following some pre-monsoon showers.

Surya Prakash, a zoologist studying butterflies in the region for more than three decades, believes this year's climatic fluctuations have triggered early migration.

"While these butterflies breed in the Himalayan region in April, we started seeing them around the end of February and are now being seen in large numbers. The Large Cabbage White and Asian Cabbage White were still missing at the same time last year, but high temperatures in February followed by a wet March has led to the early bloom of flowers, which may have also caused these butterflies to breed early, as caterpillars can sense temperature changes even in the pupa stage," said Prakash, a retired professor from Jawaharlal Nehru University (JNU).

These observations, according to Prakash, are fairly consistent across the NCR at locations such as JNU, Sanjay Van, Asola Bhatti Wildlife Sanctuary, both Aravalli Biodiversity Parks in Gurugram and Delhi, Surajpur wetlands, Dhanauri, and Mangar.

The butterfly breeding and migration cycle coincides with flowers blooming, allowing them to feed on nectar. Pollination occurs as a result. Most of these flowers bloom during the summer.

From October to December, butterflies migrate from the plains to the higher reaches and Ghats, before returning to the plains between April and June. Butterflies typically arrive in Delhi from the Himalayas, where they breed until April and May.

However, early or delayed migration could harm butterfly species in the long run.

According to Faiyaz Khudsar, a scientist in charge of the Delhi Development Authority's biodiversity parks programme, "It's possible that the temperatures are high, but the host plants or flowers aren't mature enough to reproduce. Such changes in weather patterns are fine for a year or two but can impact butterflies in the long run."

The Tropical Indian Fritillary, a butterfly seen in the Himalayas, is another rare sighting in Delhi-NCR.

According to Chandra Bhushan Maurya, a birder and butterfly enthusiast, the Tropical Indian Fritillary was spotted at a roundabout near Janpath, and that early flower bloom, combined with good rain, may have facilitated early breeding this year.

"February was warm, but rains in March caused most flowers to bloom, allowing these butterflies to breed in abundance. As a result, even the resident butterfly population, such as Plain Tiger, Striped Tiger, Pioneer, and Pea Blue, is larger than usual," he said.

According to Khudsar, the presence of butterflies indicates a healthy environment and ecosystem. "Their population is an excellent predictor of climate change. Their role in pollination is also vital," Khudsar added.

Prakash believes that planting abundant flowers as part of the G-20 summit preparations in Delhi has also contributed to the increased population of butterflies.

"Because the Tropical Indian Fritillary is drawn to ornamental flowers, it's no surprise that it was spotted in one of these flower beds," Prakash said. "Butterflies are also finding suitable host plants among the flowers that have been planted," he added.

Butterfly effect

Migration pattern

Butterflies migrate from the plains to the Ghats or the Himalayas in October-December using northeast monsoon wind currents. They return to the plains in April-June, before the southwest monsoon. These butterflies breed in mountains, and their offspring come to the plains to begin the cycle again.

Species being seen early and in large numbers

Painted Lady, Asian Cabbage White and the Large Cabbage White, Blue Tiger

Rare migration sighting

Tropical Indian Fritillary

Factors leading to early migration this year

Delhi saw an unusually dry and warm February, followed by a wet March, allowing for flowers to bloom early.

Experts said not only were flowers available in abundance, but this weather pattern also mimicked the April to May period, where pre-monsoon showers follow dry summer period.

Delhi has also seen plantation of many flowers as part of G20 preparations, which is bringing more butterflies.

Blue Tiger
Chandra Bhushan Maurya

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 22 अप्रैल 2023 ----------DATED----------

साल के अंत में मिलेंगे 5 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

द्वारका के अलग-अलग सेक्टरों में हो रहा है निर्माण

■ विशेष संवाददाता, द्वारका

द्वारका को इस साल के अंत तक पांच नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलने की उम्मीद है। इन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर तेजी से काम चल रहा है। सेक्टर-17 में बन रहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग तैयार है। वहीं सेक्टर-8, 19, 19बी और 23 में बन रहे कॉम्प्लेक्स का काम भी एडवांस स्टेज में चल रहा है।

पांच नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बन जाने से यहां मौजूद सेक्टर-11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर दबाव कम होगा। नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नई सुविधाओं के साथ कई खेलों की भी सुविधाएं हैं। डीडीए के अनुसार यह सभी प्रोजक्ट इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे।

द्वारका सेक्टर-17

23.71 एकड़ में फैला यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर लगभग तैयार है। फायर एनओसी और पानी का कनेक्शन न मिलने की वजह से अभी इसे शुरू नहीं किया जा सका है। 92 करोड़ की इस परियोजना में क्रिकेट फील्ड, हॉकी फील्ड, टेनिस कोर्ट, स्केटिंग रिंग, जॉगिंग ट्रैक व वॉलीबॉल ग्राउंड समेत कई अन्य कई सुविधाएं हैं।

द्वारका सेक्टर-8

यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बॉक्सिंग, कुश्ती व जूडो-कराटे से जुड़े खेलों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 23.31 एकड़ में बन रहे इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम

लगभग 75 प्रतिशत तक पूरा हो गया है। जून 2023 तक इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

द्वारका सेक्टर-23

हॉकी व फुटबॉल के लिए केंद्रित इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल के लिए ऑडियो-विजुअल रूम के साथ लेक्चर रूम की सुविधा भी है। यहां स्केटिंग रिंक, जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने के लिए क्षेत्र, स्पोर्ट्स सेंटर, कैफेटेरिया आदि होंगे। इस कॉम्प्लेक्स का 70 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।

■ सेक्टर-17 में बन रहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग तैयार है।

■ सेक्टर-8, 19, 19बी और 23 में काम एडवांस स्टेज में है

द्वारका सेक्टर-19

टेनिस व शूटिंग के लिए बन रहे इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शूटिंग रेंज, बैडमिंटन हॉल, स्क्वैश कोर्ट, समेत कई अन्य सुविधाएं होंगी। इसका 65 प्रतिशत काम हो गया है।

द्वारका सेक्टर-19बी

पीपीपी मॉडल पर डीडीए इस मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को तैयार कर रहा है। यहां 30 हजार लोगों के बैठने की क्षमता वाला क्रिकेट व फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। यह 53.52 एकड़ बन रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ दैनिक जागरण रविवार, 23 अप्रैल, 2023 ----------DATED----------

दिल बाग बाग हो जाएगा

गमले में लगा एक फूल ही इतना सुंदर होता है तो सोचो कैसी होती होगी वो दुनिया जहां सजते हों हजारों-लाखों फूल! फूलों से बनाए जाते हों पक्षी, महल और ढेरों कलाकृतियां। देश में कुछ मशहूर बाग-बगीचे हैं जहां आयोजित की जाती हैं दुर्लभ फूलों की प्रदर्शनियां व होती हैं प्रतियोगिताएं...

फूलों से होती है हर जगह सजावट, मगर जब हरकदम पर खुद फूल ही सज रहे हों तो सोचो क्या गजब नजारा होता होगा। दरअसल, देशभर में कई ऐसी जगहें हैं जहां फूलों के उत्सव और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। **फूलों की खेती को बढ़ावा देने, भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्धि व कलाकृति को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विभिन्न रंगों और प्रकारों में फूलों के पौधे प्रदर्शित किए जाते हैं।** इस वर्ष तो जी20 आयोजनों में भी तमाम शहरों में फूलों की प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। गर्मी की छुट्टियां बस होने ही वाली हैं तो क्यों न इस बार अनुभव कर लो फूलों की प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं का।

ट्यूलिप से सजा है धरती का स्वर्ग

धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में इन दिनों जारी है ट्यूलिप फेस्टिवल। एशिया के इस सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में इतने प्रकार के ट्यूलिप सजते हैं कि इंद्रधनुष के रंग भी कम पड़ जाएं। श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में हर वर्ष मार्च-अप्रैल में आयोजित होने वाला ट्यूलिप फेस्टिवल वर्ष 2007 में शुरू हुआ था। इस वर्ष यहां ट्यूलिप के लगभग 16 लाख फूलों के साथ 68 अलग-अलग किस्मों के फूल खिले हैं। डल झील के पास पहाड़ों की तलहटी में ट्यूलिप का सौंदर्य देखते ही बनता है।

मन मोह लेती हैं कलाकृतियां

देश में फूलों के कुल उत्पादन में तमिलनाडु की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत है। यहां ऊटी के सरकारी उद्यान में आयोजित होने वाली पुष्प प्रदर्शनी देश में ऐसे सबसे सुंदर आयोजनों में से एक है। वर्ष 1847 में यहां पहली पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। हर साल यहां 15,000 से ज्यादा फूलों वाले पौधों व अनगिनत फूलों की मदद से चित्ताकर्षक कलाकृतियां बनाई जाती हैं। यह प्रदर्शनी आमतौर पर मई में आयोजित की जाती है। इसके साथ ही यहां गुलाब शो भी आयोजित किया जाता है।

फूलों का लगता मेला

बेंगलुरु में लालबाग फ्लावर शो का इतिहास बहुत पुराना है। लालबाग बाटेनिकल गार्डन को टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने विकसित करवाया था। बाद में टीपू सुल्तान ने भी इसकी देखभाल की। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने इसे गवर्नमेंट बाटेनिकल गार्डन का दर्जा दिया। यहां हर साल गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस पर फ्लावर शो आयोजित किया जाता है। हर बार यहां फूलों की मदद से मैसूर पैलेस, ताजमहल, लाल किला, लोटस टेंपल जैसी मशहूर इमारतों की प्रतिकृतियां तैयार की जाती है, जो वाकई देखने लायक होती है।

ट्यूलिप की डेढ़ों किस्में इन दिनों खिली हुई हैं कश्मीर में

लालबाग फ्लावर शो में फूलों से तैयार कलाकृति

देश के दिल में महक फूलों की

देश की राजधानी नई दिल्ली में अनेक पुष्प प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। इनमें सबसे ऊपर है राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान और सबसे अद्भुत है गणतंत्र दिवस पथसंचलन में पुष्पों से तैयार सचल झांकियां। इनके अतिरिक्त भी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विश्वविद्यालय और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के सहयोग से प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। इसी तरह दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में शामिल नोएडा और गुरुग्राम में भी फ्लावर शो आयोजित किए जाते हैं। यहां सरकारी-गैर सरकारी संस्थान और फूल-पौधों के प्रेमी शामिल होते हैं।

चंडीगढ़ के प्रसिद्ध क्रिसैंथेमम शो में कई स्थानीय फूल-पौधों के साथ मुख्य रूप से गुलदाउदी के फूलों को प्रदर्शित किया जाता है। 15 वर्ष से जारी इस आयोजन में घरों से लाए गए 10,000 से अधिक गमले प्रदर्शित किए जाते हैं।

दुर्लभ पुष्पों का अंतरराष्ट्रीय उत्सव

गंगटोक (सिक्किम) में हर साल अप्रैल और मई के महीने में अंतरराष्ट्रीय फूल उत्सव आयोजित किया जाता है। ये देश में होने वाले सर्वश्रेष्ठ फूल उत्सवों में से एक है, जहां 515 किस्म के दुर्लभ आर्किड, 36 रोडोडेंड्रन, मैग्नोलिया, ग्लेडियोलस की अनोखी प्रजातियां प्रदर्शित की जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों से यहां अंतरराष्ट्रीय फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 20 से अधिक देश शामिल हो चुके हैं। इसी तरह मेघालय में वार्षिक तौर पर आटम फ्लावर शो आयोजित होता है, जो मुख्य रूप से अक्टूबर और नवंबर के बीच शिलांग में आयोजित होता है।

आरती तिवारी

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक जागरण नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2023 DATED

30 जून तक हर हाल में साफ करें यमुना : एलजी

यमुना नदी में प्रदूषण कम करने के लिए उपराज्यपाल ने मिशन मोड में काम करने का दिया निर्देश

- उच्च स्तरीय समिति की बैठक में उपराज्यपाल ने यमुना सफाई के लिए हुए कार्यों की समीक्षा की
- जून तक 95% सीवरेज का शोधन सुनिश्चित करने का निर्देश, अभी 75% सीवरेज का हो पाता है शोधन

अपनी बदहाली पर आसू बहाती यमुना...पिछले दिनों झाग वाले केमिकल्स युक्त पानी से आइटीओ यमुना घाट पर कुछ इस तरह नजर आ रही थी नदी। हर साल सरकार यमुना की सफाई पर करोड़ो रुपये खर्च करती है, लेकिन यह आज भी बदहाल है • जागरण आर्काइव

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: यमुना की सफाई के लिए एनजीटी द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में चौथी बैठक हुई। इस दौरान उपराज्यपाल ने यमुना सफाई के लिए अब तक हुए कार्यों और आठ विशेष लक्ष्यों के तहत जारी निर्देश पर कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की। इस दौरान 30 जून तक हर हाल में यमुना की सफाई और नदी में प्रदूषण कम करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए संबंधित एजेंसियों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल बोर्ड व दिल्ली सरकार के कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में अधिकारियों ने उपराज्यपाल को बताया कि नजफगढ़ नाले की सफाई के प्रयास जब से शुरू हुए हैं, तब से नाले में बीओडी (बायोलाजिकल आक्सीजन डिमांड) के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। कश्मीरी गेट के पास भी यमुना नदी के पानी में बीओडी का स्तर कम हो रहा है। उपराज्यपाल ने इस सुधार को निरंतर बनाए रखने का निर्देश दिया।

शोधन क्षमता बढ़ाई जाएगी: दिल्ली में मौजूदा समय में प्रतिदिन 768 एमजीडी सीवरेज उत्पन्न होता है। जिसमें से केवल 580 एमजीडी (75.5 प्रतिशत) सीवरेज का ही शोधन हो पा रहा है। एचएलसी ने जून तक 727 एमजीडी (95 प्रतिशत) सीवरेज शोधन सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

वहीं इस वर्ष के अंत तक सीवरेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) की शोधन क्षमता बढ़ाकर 814 एमजीडी व अगले वर्ष जून तक सीवरेज शोधन क्षमता 964.5 एमजीडी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ओखला, दिल्ली गेट और सोनिया विहार में तीन नए एसटीपी (सीवरेज शोधन संयंत्र) के निर्माण के साथ-साथ विभिन्न जगहों पर 40 नए विकेंद्रीकृत एसटीपी के निर्माण की योजनाओं, तीन मौजूदा एसटीपी के नवीनीकरण, 18 मौजूदा एसटीपी को अत्याधुनिक बनाने के काम की निगरानी समिति कर रही है। इनमें से कई परियोजनाएं भूमि आवंटन नहीं हो पाने के कारण आठ वर्षों से लंबित थी। उपराज्यपाल के हस्तक्षेप से पिछले एक माह में भूमि आवंटन का कार्य पूरा हो गया है।

यमुना सफाई के आठ लक्ष्य

1. शत प्रतिशत सीवरेज का शोधन
2. सभी नालों से यमुना में सीवरेज का प्रवाह रोकना
3. सभी अनधिकृत और जेजे कालोनियों में सीवर नेटवर्क का निर्माण
4. सीईटीपी (कामन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) के माध्यम से औद्योगिक कचरे का प्रबंधन
5. सेप्टेज प्रबंधन
6. यमुना के बाढ़ वाले क्षेत्रों का कायाकल्प
7. सीवरेज के उपचारित जल का दोबारा उपयोग
8. नजफगढ़ झील की पर्यावरण प्रबंधन योजना शामिल थी।

दिसंबर तक 239 कालोनियां सीवर नेटवर्क से जुड़ जाएंगी: एचएलसी की सक्रियता बढ़ने के बाद मार्च तक 102 अनधिकृत कालोनियों में सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है। 161 कालोनियों में जून तक सीवर लाइन बिछाया दिया जाएगा। इसके बाद सितंबर तक 71 अतिरिक्त कालोनियां और दिसंबर तक 239 कालोनियां सीवर नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। इससे 1,799 अनधिकृत कालोनियों में से 1,320 कालोनियां इस वर्ष दिसंबर तक सीवर लाइन के नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। 81 जेजे क्लस्टर, जहां सीवरेज लाइन बिछाना संभव नहीं है वहां जून तक नमामि गंगे परियोजना के सहयोग से प्री-फैब्रिकेटेड विकेंद्रीकृत एसटीपी बनाए जाएंगे। बैठक में एलजी ने सेप्टेज प्रबंधन के लिए पंजीकृत 180 टैंकर को जीपीएस से लैस करने का निर्देश दिया।

उपचारित पानी के दोबारा इस्तेमाल की योजना तैयार करने का निर्देश: मौजूदा समय में 580 एमजीडी उपचारित सीवरेज के पानी में से 267 एमजीडी पानी वापस नदी में डाला जाता है। 90 एमजीडी उपचारित पानी का ही दोबारा इस्तेमाल बागवानी के लिए होता है। 100 एमजीडी उपचारित पानी पल्ला ले जाकर वापस उच्च गुणवत्ता तक शोधित करने की योजना है। शेष 123 एमजीडी उपचारित पानी नजफगढ़ झील, स्मृति वन झील और एनटीपीसी इको पार्क में भंडारण करने का एचएलसी ने निर्देश दिया था। इस योजना का अगस्त तक काम पूरा होने की उम्मीद है। बैठक में एलजी ने जल बोर्ड को सीवरेज के 800 एमजीडी उपचारित पानी के दोबारा इस्तेमाल की योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 23 अप्रैल 2023

6 दिवसीय एमपी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन

■ प्रस, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया विजन के तहत दिल्ली के अलग-अलग जिलों में सांसदों की ओर से एमपी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। वेस्ट दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह की देखरेख में इस जिले में भी फेस्टिवल का आयोजन हुआ। अलग-अलग खेल प्रतियोगिताओं में 180 स्कूलों के स्टूडेंट्स ने भाग लिया। 1200 विजेताओं को सम्मानित किया गया।

खेल प्रतियोगिताओं में 180 स्कूलों के स्टूडेंट्स ने भाग लिया

सांसद प्रवेश साहिब सिंह के अनुसार एमपी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन 14 (अंबेडकर जयंती) से 20 अप्रैल के बीच किया गया था। पहले दिन मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें 3 हजार से अधिक स्टूडेंट्स ने भाग लिया। खेल प्रतियोगिताओं में लॉन टेनिस, क्रिकेट, बॉस्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो-खो, मार्शल आर्ट, एथलेटिक्स, फुटबॉल, स्किपिंग, टेबल टेनिस, शतरंज जैसे आउटडोर और इंडोर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एमपी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का समापन 20 अप्रैल को द्वारका के डीडीए खेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस दौरान करीब 4 हजार लोग उपस्थित रहे।

* SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
APRIL 23, 2023

Several key tasks missed deadlines: NGT panel

Kushagra.Dixit@timesgroup.com

New Delhi: The high-level committee on Yamuna, formed on the directions of the National Green Tribunal (NGT) to oversee the river's rejuvenation within a fixed timeframe, has pointed out that several deadlines of essential tasks that were to be completed by March-end have been missed.

The panel, headed by the lieutenant governor, held its third meeting on March 14, the minutes of which were made available recently.

According to the committee, less than a fourth of the sub-drains falling in Najafgarh drain could be trapped.

"Out of 76 sub-drains, 18 falling into Najafgarh drain have been trapped, against a target of 26. Out of 573 unauthorised colonies where the laying of sewage network is under progress, work has been completed in 42, against a target of 102. Out of 200km, about 22km of desilting of trunk/peripheral sewer has been completed, against a target of 50km," stated the minutes of the meeting.

However, 17 out of 81 JJ clusters received sewer connections, against a target of 13, the panel added.

Among action points for February that were found to be lagging were removal of encroachment from a 5.7-hectare plot from DDA's Asita West project on Yamuna floodplains, and allotment of land for a 10 MGD sewage treatment plant at Delhi Gate and decentralised STPs.

On the positive side, the committee said the city's sewage treatment capacity will reach 95% by June and 106% by December. Currently, Delhi generates 768 MGD sewage daily, of which only 530 MGD, or 69%, is treated.

On January 11, NGT had expressed dissatisfaction with the revival of the Yamuna and constituted a high-level committee led by the lieutenant governor. The committee is scheduled to meet every week, take stock of the situation and track the goals to substantially improve the quality of the river by July this year.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS— दैनिक जागरण नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2023 TED

निगम के पास नहीं रहेंगी 60 फीट चौड़ी सड़कें

इन सड़कों की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी है पीडब्ल्यूडी के पास, अब सफाई भी करवाएगा विभाग

निहाल सिंह • नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में 60 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों की साफ-सफाई का जिम्मा भी दिल्ली सरकार के पास जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को सौंपने की तैयारी तेज है। दिल्ली सरकार इन सड़कों की सफाई पीडब्ल्यूडी से कराने का निर्णय ले चुकी है। अब गेंद दिल्ली नगर निगम के पाले में है। नगर निगम की 26 अप्रैल को होने वाली बैठक के प्रस्ताव में इस मामले को भी सूचीबद्ध किया गया है। वैसे, उसी दिन महापौर का चुनाव भी होना है। पूर्व की तरह इस चुनाव में आप प्रत्याशी की जीत होने पर बहुमत के आधार पर यह प्रस्ताव भी पारित हो जाएगा, क्योंकि सरकार के निर्णय के आधार पर ही सदन में प्रस्ताव लाया गया है। फिलहाल राजधानी में पीडब्ल्यूडी की 1,440 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जिनका रखरखाव वह खुद करता है, लेकिन साफ-सफाई का जिम्मा नगर निगम के पास है। इसी काम को भी पीडब्ल्यूडी को सौंपने का प्रस्ताव निगम सदन में आएगा।

वर्ष 2012 में गया था रखरखाव का जिम्मा: वर्ष 2012 में दिल्ली सरकार ने 60 फीट और उससे अधिक चौड़ी सड़कों के रखरखाव का जिम्मा पीडब्ल्यूडी को दे दिया था और सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपा गया था। वहीं, इससे कम चौड़ी सड़कों का रखरखाव और सफाई, दोनों नगर निगम के पास है।

>> रोड स्वीपर • जागरण आर्काइव

भाजपा ने दिल्ली को बना दिया कूड़े का शहर : आप

आप का कहना है कि भाजपा ने 15 वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी को कूड़े के शहर में तब्दील कर दिया है। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को साफ करने का रोल आउट प्लान बनवा रहे हैं, तो भाजपा को परेशानी हो रही है।

26 अप्रैल को होने वाली नगर निगम की बैठक में इस प्रस्ताव को किया गया सूचीबद्ध

किसके पास कितनी लंबी सड़कें

एजेंसी	लंबाई
लोक निर्माण विभाग	1,440 किमी
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	3.2 किमी
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	835 किमी
नगर निगम	15,582 किमी
डीएसआइडीसी	314.5 किमी
एनडीएमसी	135 किमी
डीडीए	340 किमी

आप से नहीं संभल रहा निगम, इसलिए ऐसा हो रहा है : भाजपा

नगर निगम के प्रस्ताव पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। उसने कहा है कि नगर निगम की सत्ता आप से संभल नहीं रही है और सफाई कराने में महापौर विफल साबित हो रही है। इसलिए अब सफाई का काम पीडब्ल्यूडी को सरकार देना चाहती है, जबकि साफ-सफाई ही नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि जो कर्मचारी अनुबंध पर काम कर रहे हैं, इस प्रस्ताव से उनकी नौकरी पर संकट आ जाएगा, क्योंकि काम कराएंगे नहीं तो वेतन कैसे देंगे। पीडब्ल्यूडी के पास एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है।

क्या होगा नुकसान

- इन सड़कों से मलबा उठाने के लिए निगम ने पहले ही विभिन्न एजेंसियां प्रत्येक जोन में लगा रखी है। ऐसा होने पर वह कंपनियां कोर्ट में जा सकती हैं।
- यहां पर जो सफाईकर्मी काम करते हैं, उन्हें दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करना पड़ेगा, यार्ड स्टिक के हिसाब से इन कर्मियों की संख्या निगम के पास सरप्लस हो जाएगी।
- नगर निगम ने पहले ही इन सड़कों की सफाई के लिए 52 मैकेनिकल स्वीपर लगा रखे हैं, जो अनुपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि वह ट्रक के आकार के हैं और वह निगम के पास 60 फीट से छोटी सड़कों पर नहीं चल पाएंगे।
- नगर निगम ने 18 और मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेज रखा है, जिसे रद कराना पड़ेगा।
- उपराज्यपाल के निर्णय के अनुसार इन सड़कों पर रोड कटिंग की इजाजत भी नगर निगम ही देता है।

क्या होगा फायदा

- अभी इन सड़कों की मरम्मत से लेकर रखरखाव का काम पीडब्ल्यूडी के पास है। एक ही एजेंसी दोनों काम देखेगी, तो संभवत इसमें और सुधार होंगे।
- नगर निगम के पास रिहायशी इलाकों की सफाई बचेगी। ऐसे में नगर निगम वहां अपने संसाधनों को इन सड़कों से हटाकर लगाएगा, तो रिहायशी इलाकों की सफाई बेहतर हो सकती है।
- फंड की कमी से जूझ रहे नगर निगम के पास इन सड़कों की सफाई के लिए होने वाला खर्च कम होगा, तो इससे वह दूसरे विकास कार्य भी कर सकेगा।
- सरकार के पास फंड की कमी नहीं है, जिससे वह इन सड़कों की सफाई के लिए नई-नई मशीनरी भी जरूरत के हिसाब से जल्द खरीद सकेगी।

नगर निगम ने टिप्पणियों के साथ रखा है प्रस्ताव : दिल्ली सरकार की ओर से आए मसौदे को नगर निगम ने सदन के सामने रख जरूर दिया है, लेकिन इस पर कई टिप्पणियां भी की हैं। इसमें एक यह कि निगम का प्राथमिक कार्य ही सफाई है। ऐसे में इसमें बदलाव एलजी की मंजूरी से ही किया जा सकता है। वैसे, नगर निगम ने दिल्ली सरकार के इस निर्णय का सीधे विरोध नहीं किया है, लेकिन यह अवश्य कहा है कि वह सफाई से जुड़े कार्य करने में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने हाल ही में ऐलान किया था कि वह सड़कों की धुलाई और सफाई कराएगी। साथ ही हर विधानसभा के लिए एक-एक मैकेनिकल स्वीपर खरीदने का प्रविधान भी बजट में किया था।

क्या-क्या दिल्ली सरकार के पास चला गया : दिल्ली विधानसभा गठन से पहले नगर निगम के पास पानी से लेकर बिजली, स्लम, परिवहन और फायर सर्विस जैसे विभाग थे, लेकिन वर्ष 1971 में परिवहन को अलग कर दिया था। इसके लिए दिल्ली परिवहन निगम नामक एक स्वतंत्र प्राधिकरण बनाया था। वर्ष 1993 में दिल्ली नगर निगम एक्ट में संशोधन के जरिये बिजली और पानी भी सरकार के अधीन हो गया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2023 दैनिक जागरण DATED

एआरएचसी योजना लागू होने के बाद तय होगा 9,535 फ्लैटों का भविष्य

वी के शुक्ला • नई दिल्ली

- तैयारी पूरी, एक माह के अंदर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच होगा एमओयू
- 2020 में केंद्र की एआरएचसी योजना की घोषणा के बाद इसे रोक दिया गया था

गरीब झुग्गीवासियों को किराये पर देने के लिए 9,535 फ्लैट दिल्ली सरकार को मिल पाएंगे या नहीं, यह फैसला अब अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काम्प्लेक्स (एआरएचसी) योजना के लागू होने के बाद तय होगा। लगभग तीन वर्ष से लटकी इस योजना को लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने साफ किया है कि पहले इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी, उसके बाद ही इस बारे में निर्णय किया जाएगा। दरअसल, दिल्ली सरकार ने स्लम निवासियों के लिए आवंटन प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन वर्ष 2020 में केंद्र की एआरएचसी योजना की घोषणा के बाद इसे रोक दिया गया था। पिछले कुछ वर्षों में यूपीए-युग की योजनाओं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाइ) के तहत इन फ्लैटों का निर्माण किया गया है।

दिल्ली सरकार के पास गरीबों के लिए 45,000 में से 36,000 फ्लैट तैयार हैं। अब इन्हें एआरएचसी योजना के तहत गरीबों को किराये पर दिया जाना है। लेकिन, 18,639 फ्लैटों के लिए अभी तक एआरएचसी योजना लागू नहीं हो सकी है। दिल्ली सरकार ने कई बार केंद्र को पत्र लिखकर केंद्र से 18,639 फ्लैटों को एआरएचसी योजना से बाहर करने का अनुरोध किया है। इनमें से 9,535 फ्लैट दिल्ली सरकार को चाहिए, इनके लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) आवंटन प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका है। इनके लिए झुग्गीवासियों को फ्लैट देने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। दिल्ली सरकार चाहती है कि जिन लोगों को फ्लैट देने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, उन्हें फ्लैट दे दिए जाएं। 18,639 में से 9,104 डीडीए ने मांगे हैं। दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि एआरएचसी योजना लागू करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।

एक माह के अंदर इस योजना को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि इन फ्लैटों का किराया कितना होगा। उन्होंने कहा कि यह पूर्व निर्धारित है कि ये फ्लैट झुग्गीवासियों को ही किराये पर दिए जाएंगे और धीरे-धीरे दिल्ली से झुग्गियां हटाई जाएंगी। योजना के तहत अब दिल्ली में जल्द ही गरीबों को किराये पर सरकारी फ्लैट मिल सकेंगे।

दिल्ली सरकार इस योजना को लेकर केंद्र सरकार के साथ जल्द एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। दिल्ली सरकार का डूसिब (शहर में शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी) इस योजना पर काम कर रहा है। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लाकडाउन के समापन के बाद प्रवासी शहरी गरीबों को किराये पर आवास देने के लिए केंद्र ने एआरएचसी योजना शुरू की थी।

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 24 अप्रैल 2023

हरि नगर में खालसाई खेल

■ **विस, नई दिल्ली:** सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया की तीसरी जन्म शताब्दी को समर्पित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी की ओर से वेस्ट दिल्ली में खालसाई खेलों का आयोजन किया गया। निहंग सिंहों ने गतकों के अलावा घोड़ों पर सवार होकर कई हैरतंगेज करतब दिखाए। हरि नगर के डीडीए पार्क में हुए समागोह में मनजीत सिंह जीके के अलावा परमजीत सिंह सरना और अन्य सिख नेता पहुंचे।

हिन्दुस्तान

डीडीए फ्लैट्स में हजारों परिवार पानी के लिए तरसे

- 1350 एलाईजी फ्लैट्स हैं न्यू कोंडली इलाके में
- निजी टैंकर से पानी मंगाना पड़ रहा

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी दिल्ली के मयूर विहार स्थित न्यू कोंडली इलाके में बने 1350 डीडीए एलाईजी फ्लैट्स के निवासी पानी न आने की समस्या से बेहद परेशान हैं। यहां रहने वाले परिवारों का कहना है कि डीडीए और जल बोर्ड के अधिकारियों से शिकायत के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

आरडब्ल्यूए के महासचिव राहुल ठाकुर ने बताया कि सप्लाई का पानी बहुत कम आता है। 500 रुपये जमा कर निजी टैंकर से पानी मंगवाना पड़ रहा है। राहुल ने बताया कि डीडीए हर माह 363 रुपये पानी का शुल्क भेजता है, लेकिन पानी नहीं आता। ऐसे में यहां रहने वाले करीब 1200 परिवारों के लगभग पांच हजार लोग परेशान हैं।

कई बार शिकायत देने के बाद भी समाधान नहीं: स्थानीय निवासी अंकित ने बताया कि डीडीए और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ कई बार बैठक हुई है। कई बार शिकायत पत्र लिखे गए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। राहुल ने बताया कि जल बोर्ड कहता है कि डीडीए ने पानी का बकाया नहीं दिया है। समस्या का समाधान न होने पर सोशल मीडिया पर अपने हक के लिए अभियान चलाया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER हिन्दुस्तान नई दिल्ली सोमवार 24 अप्रैल 2023 ----DATED----

बारिश के पानी को तालाबों और भूमिगत रिचार्ज पिट तक पहुंचाया जाएगा

जलभराव रोकने के लिए जलाशयों से जुड़ेंगे नाले

सुविधा

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मानसून के लिए तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी को जलभराव से बचाने के लिए नालों को जलाशयों से जोड़ा जाएगा। इससे भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

डीडीए दिल्ली के कई इलाकों में स्टॉर्म वाटर ड्रेन और ट्रंक ड्रेन बनाएगा। इसके जरिए जलभराव वाले स्थानों से बारिश के पानी जलाशयों तक पहुंचाया जाएगा। कई जगहों पर काम भी शुरू कर दिया गया है।

दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव बड़ी समस्या बन जाती है। लोक निर्माण विभाग ने इससे निपटने के लिए अपने इलाके में तैयारी भी शुरू कर दी है। जलभराव वाले 165 स्थानों को चिह्नित किया गया है। वहीं, डीडीए ने बारिश के पानी का इस्तेमाल भूजल स्तर को बढ़ाने में करेगा। डीडीए स्टॉर्म वाटर ड्रेन और ट्रंक ड्रेन बना रहा है, जिससे बारिश के पानी को जलाशयों, रिचार्ज पिट, पार्कों तक ले जाया जाएगा। उधर, दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं कि मानसून से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि दिल्लीवालों को असुविधा न हो। डीडीए की इन योजनाओं पर उच्चस्तर से नजर रखी जा रही है।

पीडब्ल्यूडी ने मानसून से पहले तैयारी का दावा किया

165 स्थान जलभराव वाले चिह्नित

130 करोड़ रुपये की योजना डीडीए ने तैयार की

इन इलाकों को फायदा

- पालम
- इंदिरा गांधी हवाई अड्डा
- द्वारका
- रोहिणी
- किराड़ी

- सात किलोमीटर लंबी ट्रंक ड्रेन रोहिणी में बनाई जाएगी, जिस पर 100 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है

द्वारका के लिए 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे

डीडीए एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन द्वारका सेक्टर-8 में बना रहा है। इसके बनने से हवाई अड्डे से निकलने वाले अतिरिक्त पानी को द्वारका के सेक्टर-8 और सेक्टर-23 के पार्कों में बने जल निकायों, रिचार्ज पिट तक ले जाएगा। इससे द्वारका सेक्टर-8, राजनगर, बगडोला और पालम क्षेत्र में बारिश के पानी के कारण होने वाले जलभराव से निजात मिलेगी और भूजल स्तर में भी सुधार होगा। इस योजना पर डीडीए 30 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च कर रही है।

इनके लिए भी प्रस्ताव तैयार

डीडीए रोहिणी में सेक्टर-20, 21, 22 और अविकसित सेक्टर-39, 40, 41 की खाली जमीन पर तथा किराड़ी विधानसभा के अनधिकृत 10 कॉलोनी में जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए 7.2 किलोमीटर लंबी ट्रंक ड्रेन बनाने का प्रस्ताव है। इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, जल निकायों के कायाकल्प के लिए भी योजना तैयार की है। इसमें सीवेज शोधन संयंत्रों के पानी का अधिक से अधिक उपयोग करके जल निकायों तक पानी पहुंचाया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI MONDAY, APRIL 24, 2023 DATED

Idea takes root: NDMC plans horticulture training for RWAs and market associations

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Having imparted training to the horticulture staff of various government departments and institutions in Delhi-NCR for over a decade, the New Delhi Municipal Council (NDMC)'s School of Gardening plans to provide the same opportunity to Residents Welfare Associations (RWAs) and market associations.

It aims to hold workshops so that they can contribute to beautifying their neighbourhood parks and markets with theme-based plantations and improving the overall aesthetic of the place.

NDMC vice-chairman Satish Upadhyay said, "The NDMC's School of Garden is known for its expertise in horticulture skills. Recently, 125 section officers and 100 *malis* of DDA were given training. Prior to this, 200 *malis* of the erstwhile East Corporation were given training last year. Considering we have the facility in place, a proposition will be given to the NDMC chairman to organise training of RWAs and market traders associations in the NDMC area on kitchen, terrace, vertical gardening, and composting."

"With its resources, NDMC can also organise crash courses in flower arrangements, bonsai and vertical gardening for the general public," said Upadhayay. "People can earn their livelihoods by learning these skills."

The School of Gardening was established in 2011 to provide practical training to field staff and help them interact with the best horticulturists, botanists, foresters and gardeners.

NDMC VICE-CHAIRMAN SAYS

With its resources, NDMC can also organise crash courses in flower arrangements, bonsai and vertical gardening for the general public

It is known for providing training in 24 streams, including layout and design of gardens, vertical gardening, hydroponic farming and macro irrigation techniques through certified trainers," said senior NDMC officials and experts.

Since its inception, several training programmes on the latest techniques and innovations, including for 2,000 staff of the erstwhile South Corporation, ITPO, and RMR workers of NDMC, have been conducted here, said officials.

NDMC has 64.5% green cover with six major gardens and three international relationship memorial parks. In addition to this, there are five rose gardens, 135 avenues of 270 km length, eight nurseries, three hi-tech nurseries, 51 roundabouts, three happiness parks, 24 vertical gardens at different locations, 123 residential parks, and 500 CPWD colony parks.

"We have 1.8 lakh trees that are decades old and to check their health we have trained staff for tree surgery," said the official.

In 2016-17, the school sent its senior officials and malis to Singapore, China and Belgium to get hold of practices adopted worldwide in horticulture.

"At these places, staff learnt the concept of tissue culture (in China), topiary and city landscaping (in Belgium), and vertical gardening of different sizes (in Singapore). The use of machines for tree surgery and hydroponic and aeroponic farming was also learnt in detail here," said an official.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

DATED

नई दिल्ली। शनिवार • 22 अप्रैल • 2023 | सहारा

एलजी साहब राजधानी में क्या हो रहा है : मुख्यमंत्री

नई दिल्ली (एसएनबी)। साकेत कोर्ट में गोली बारी की घटना के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा कि राजधानी में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस घटना का एक वीडियो साझा करते हुए उन्होंने सवाल किया, 'उपराज्यपाल साहब, राष्ट्रीय राजधानी में यह क्या हो रहा है?' उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'राजधानी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है। दूसरों के कामों में अड़चन पैदा करने और हर बात पर गंदी राजनीति करने की बजाए सभी को अपने-अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई इसे संभाल नहीं पा रहा, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कोई और इसकी जिम्मेदारी ले सके। लोगों की सुरक्षा रामभरोसे नहीं छोड़ी जा सकती।

- लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती : केजरीवाल
- सुरक्षित राजधानी बनाने पर ध्यान केंद्रित करें एलजी : आतिशी

उधर शिक्षा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर केजरीवाल सरकार के काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए उनसे राजधानीवासियों को एक सुरक्षित शहर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया है। उनकी यह टिप्पणी साकेत अदालत परिसर में गोली चलने की घटना के मद्देनजर आई है। शुक्रवार को साकेत अदालत के अंदर एक शख्स ने महिला को गोली मार दी। शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते आतिशी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी बेहद शर्मनाक घटना की गवाह बनी। हम सभी जानते हैं यहां महिलाएं कभी सुरक्षित नहीं रही हैं। बेहद सुरक्षित इलाके में एक महिला को कई गोलियां मारी गईं। यह घटना राजधानी में दिन के उजाले में हुई, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर में अदालत परिसर सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में शुमार होता है। यहां पुरुष और महिला पुलिसकर्मी, पीसीआर वैन, मेटल डिटेक्टर और स्कैनर हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी महिला को गोली मार दी गई। आतिशी ने कहा कि मैं आपसे आग्रह करती हूं कि अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों को एक सुरक्षित राजधानी प्रदान करने की दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करें।

स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना की जिम्मेदारी 'लेनी चाहिए क्योंकि पुलिस उन्हें ही रिपोर्ट करती है। उन्होंने ट्वीट किया, "उपराज्यपाल साहब के दो ही काम हैं - पुलिस और डीडीए। नए उपराज्यपाल साहब के आने के बाद राजधानी की कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर हो गई है। अदालतों में गोलियां चल रही हैं। पुलिस 350 करोड़ के भ्रष्टाचार में डूबी है।

23 अप्रैल, 2023 ▸ रविवार
पंजाब केसरी

यमुना में न बहाएं प्लास्टिक कचरा जलीय जीवों को पहुंचाता है हानि

जलबोर्ड ने की लोगों से अपील, कचरा पानी की गुणवत्ता को भी खराब करता है

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): लोगों को जल संरक्षण, यमुना की सफाई व यमुना में किसी भी प्रकार का कचरा न फेंकने के लिए दिल्ली जलबोर्ड अक्सर विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करता रहता है। अब जलबोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लोगों को यमुना की सफाई एव उसमें कचरा न फेंकने की अपील की है। जलबोर्ड ने कहा कि यमुना में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक कचरा न बहाएं। यह सभी जलीय जीवों को हानि पहुंचाता है, साथ ही यह पानी की गुणवत्ता को भी खराब करता है। इतना ही नहीं जलबोर्ड ने स्लोगन आदि के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वे न तो स्वयं यमुना में किसी भी प्रकार का कचरा बहाएंगे और न ही किसी को बहाने देंगे। स्वच्छ यमुना की जिम्मेदारी अब बनेगी जिद हमारी, स्वच्छ यमुना-स्वस्थ यमुना हम सब का ध्येय है। इसमें यह भी कहा गया है हम सीवर कनेक्शन लेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जलबोर्ड ने लोगों को जल संरक्षण के बारे में भी जागरूक एवं सचेत किया है। जलबोर्ड ने कहा है कि पानी हम सबको जीवन देता है इसीलिए जीवन देने वाले पानी को कतई बर्बाद न करें। पानी की बर्बादी हम सभी पर भारी पड़ेगी। जलबोर्ड ने एक अन्य ट्वीट में यमुना में मूर्ति एवं पूजन सामग्री को न बहाने की भी अपील की है।

▸▸ यमुना में पड़ा प्लास्टिक कचरा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
SATURDAY, 22 APRIL, 2023 | NEW DELHI
NAME OF NEWSPAPERS--

SAKET COURT FIRING INCIDENT

AAP slams L-G Saxena over city's law and order

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Led by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, the AAP slammed Lieutenant Governor (L-G) V K Saxena over the city's law-and-order situation on Friday, following a shooting incident inside the Saket court complex.

No response was available from the L-G's office on the AAP's attack on Saxena.

In an apparent dig at the L-G and the BJP-led Centre, Kejriwal in a tweet said Delhi's law-and-order situation is "creaking" and instead of creating hurdles in others' jobs and indulging in dirty politics, everyone should pay attention to the job at their hands.

He also said those responsible for the situation should resign if they are not able to handle it.

People's safety cannot be left to the mercy of gods, the Aam Aadmi Party national convenor said.

Sharing a video on Twitter of the Saket court firing incident, in which a woman aged around 40 years was shot at, Kejriwal asked, "L-G sahab, what is happening in our Delhi?"

The woman, identified as M Radha, sustained bullet injuries on her abdomen and hand and was rushed to a hospital where her condition was stated to be stable, police said. The accused, a lawyer, had got a case lodged against the victim.

"The LG has only two jobs — police and the DDA. After the arrival of the new L-G sahab, the law-and-order situation in Delhi has gone from bad to worse. Bullets are being fired in courts. The police is involved in corruption involving Rs 350 crore," AAP's chief spokesperson and Delhi Health Minister Saurabh Bharadwaj said in a tweet in Hindi.

Education Minister Atishi said the incident was shameful and added that women have never been safe in the national capital.

"All of us know that women have never been safe in Delhi.

A woman was shot at multiple times in a highly-secured area. The incident took place in broad daylight, in a protected area and in the national capital. There cannot be a more shameful incident than this," she said at a press conference.

Meanwhile, senior AAP leader and Delhi minister Atishi also urged L-G V K Saxena on Friday to focus on providing a safe city to its people, while accusing him of obstructing the work of the Arvind Kejriwal government.

Addressing a press conference, Atishi said the national capital witnessed a very shameful incident.

"All of us know that women have never been safe in Delhi. A woman was shot at multiple times in a highly secured area. The incident took place in broad daylight, in a protected area and in the national capital. There cannot be a more shameful incident than this.

"In any city, a court complex is one of the most secured areas. Policemen and women, PCR vans and metal detectors and scanners are there. Despite such high security, a woman was shot at," she said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DELHI 24 अप्रैल, 2023 सोमवार

अधिकारियों की लेटलतीफी से लटका रिठाला एसटीपी का आधुनिकीकरण

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): केन्द्र और दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद यमुना प्रदूषण मुक्त नहीं हो पा रही है। इसकी एक वजह अधिकारियों की लेटलतीफी से रिठाला फेस-एक के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के आधुनिकीकरण में पांच साल का विलंब हुआ है। दिल्ली सरकार पर आरोप है कि उसने पेड़ों के स्थानान्तरण की अनुमति न देकर अपने स्वयं के एसटीपी के आधुनिकीकरण में पांच वर्षों की देरी की है। इसके चलते जनवरी 2020 से अब तक लगभग 15,000 करोड़ लीटर सीवेज का गंदा पानी यमुना में बहाया गया। यह बात यमुना की साफ-सफाई के लिए एनजीटी द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की शुक्रवार को एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामने आई। इस पर एलजी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी परियोजनाओं को जानबूझकर बाधा पहुंचाने और यमुना को जहरीला बनाने से ज्यादा आपराधिक घटना कुछ नहीं हो सकती।

एलजी के बयान पर आप का पटलवार

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : एलजी की यमुना को जहरीला बनाने वाले कथन पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि एलजी अफसरों पर जरूर कार्यवाई करें। कई अफसर आज भी कामों में देरी कर रहे है। उन पर एलजी ही कार्यवाई कर सकते है, एलजी क्या कार्यवाई करेंगे? उनके द्वारा चलाई जा रही डीडीए भी एसटीपी आदि के लिए जमीन देने में बहुत देर करती रही है, पहले भी देरी करते रहे है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में भर्तियां वर्षों से रुकी हुई हैं। वो भी एलजी के अंतर्गत आता है। क्या एलजी इस पर भी कार्यवाई करेंगे?